मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2344
15.12.2025 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पर्यावरण संरक्षण के उपाय

2344. श्री कंवर सिंह तंवर

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो जिले में चलाए गए कार्यक्रमों, उनके अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र सहित इससे प्राप्त परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण उपायों सहित विभिन्न पर्यावरण संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनएसीपी) के अंतर्गत अमरोहा जिले के मानकों को पूरा न करने वाले गजरौला शहर को वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने हेतु शहर-स्तरीय कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रिटिकल गैप फंडिंग उपलब्ध कराई गई है।

एनसीएपी के तहत वार्षिक कार्य योजना तैयार करने, उसका कार्यान्वयन करने और निगरानी करने के लिए जिला, मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। गजरौला शहर को 7.32 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा सड़क निर्माण, सड़क किनारे धूल नियंत्रण उपाय, शहरी हरित क्षेत्र विकास और जन-जागरूकता कार्यक्रम जैसे कार्य किए गए हैं। इसके अलावा शहर ने ठोस कचरे के संग्रहण, परिवहन, वर्गीकरण और जैव-अपघटन, मुख्य सड़कों का पक्का निर्माण, तथा जल छिड़काव जैसी गतिविधियाँ भी की हैं। इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के साथ मिलकर, अमरोहा जिले के तिगड़ी गंगा घाट पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता तथा गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करता है।

आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की अमृत योजना के अंतर्गत, अमरोहा शहर में 20.38 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाएँ संचालित की गईं, जिनके माध्यम से 18,333 जल के कनेक्शन और 27,300 सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान किए गए। अमृत 2.0 के अंतर्गत जिले में 151.23 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 23,585 नए जल के कनेक्शन और 13.20 एकड़ जल निकाय पुनरुद्धार शामिल है।

इसके अतिरिक्त, यूपीपीसीबी अमरोहा जिले की अत्यधिक प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का नियमित निरीक्षण करता है,जिसके साथ साथ जिला अमरोहा में औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा तीसरे पक्षकार के माध्यम से ऑडिट भी किया जाता है। मुख्य उद्योगों में सतत ऑनलाइन उत्सर्जन/प्रदूषक जल निकासी निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित है, जिन्हें यूपीपीसीबी द्वारा ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नगर वन योजना के अंतर्गत अमरोहा जिले में 160 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन/नगर वाटिका विकसित करने हेतु 6.4 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2025 में शहर द्वारा 39.95 लाख पौधे लगाए गए हैं।

इन सभी समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप, गजरौला शहर में पीएम 10 स्तर में 32.2% सुधार दर्ज किया गया है–जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 217 $\mu g/m^3$ से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 146 $\mu g/m^3$ हो गया। इसी प्रकार, एक्यूआई भी वित्तीय वर्ष 2019-20 के 132 से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 (अक्टूबर तक में 96 हो गया है।

*****